Fourth Pay Commission

689. SHRI M. BASAVARAJU: SHRI M. MADDANNA;

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 369 given in the, Rajya Sabha on the 19th March. 1985 and state-.

(a) what are the reasons for which no time limit for submission of the final report by the Fourth Central Pay Commission was prescribed in the terms of reference;

(b) whether Government propose to prescribe any time limit now; and

(o) if so. what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) On the basis of past precedents, no time limit for submission of the final report of the Fourth Central Pay Commission has been prescribed.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

12 NOON

RE. GOVERNMENT'S RESPONSE TO SPECIAL MENTIONS MADE IN THE HOUSE

MR. CHAIRMAN; Now it has been represented to me that the Ministers... will the Leader of the House hear me? It has been represented to me that the Ministers are not sending replies to the various Special Mentions which the Members make in this House. I would like the Leader of the House to take note of it and see that repties are sent and sent expeditiously.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Sir, I will extend my maximum cooperation,

SHRI K. MOHANAN (Kerala); I had raised three Special Mentions in the last session.

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट 84-85 की ओर इसके पृष्ठ 46 पर पैराग्राफ 7.15 में लिखा हुआ है -

The Minister of Parliamentary Affairs time and again reminds and requests his colleagues to get the matters raised/examined in respective Ministries Departments and send suitable replies to Members within a reasonable time, preferably within a week. The follow-up action taken by the Department

मान्यवर, इस संबंध में दो मामले जिनकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह है कि दिनांक 21 मार्च, को इसी सदन में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों को अन्तरिम राहत देने का प्रश्न मैंने उठाया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द पन्त ने एक महीने से दो दिन बाद 23 अप्रैल को अपने कार्यालय से जवाब दिया । दूसरा उदाहरण है मंडल आयोग की पिछड़े वर्गों के संबंध में सिफारिशों को लागू करने के बारे में 28 मार्च, 1985 को मैंने यह विषय इस सदन में उठाया था । इस का उत्तर माननीय गृह राज्य मंत्री ने 24 अप्रैल को दिया है । मेरा, मान्यवर, यह निवेदन है कि जो परिपाटी रही है और जो इस रिपोर्ट में दिया गया है उस का पालन नहीं हो रहा है । इस में स्पष्ट दिया हुआ है कि एक सप्ताह के अन्दर मंत्री जी को इस का उत्तर दे देना चाहिए । जैसे मैंने दो उदाहरण प्रस्तुत किये, दोनों में एक महीने से अधिक विलम्ब हुआ है ।